वायु प्रदूषण के मकड़ जाल में फंसा शहर

मनपा व शिवाजी साइंस के वार्षिक जांच की रिपोर्ट, प्रदूषण का प्रमाण बढ़ा

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती- औद्योगिक वसाहत के साथ ही शहर के निवासी क्षेत्र में भी धूल के कणों का प्रदूषण बढ़ने की जानकारी प्राप्त हुई है. महापालिका के पर्यावरण विभाग व शिवाजी उद्यान महाविद्यालय की मदद से वार्षिक जांच के बाद वायु प्रदूषण का यह कड़वा सत्य उजागर हुआ है. बढते वायु प्रदूषण पर समय पर अंकुश नहीं लगाया गया तो शहरवासियों के फेफड़ों पर विपरीत असर पड़ सकता है.

मनपा क्षेत्र में बढ़ते निवासी क्षेत्र का फटका पर्यावरण पर पड़ रहा है. शहर में वाहनों की संख्या लाखों के आसपास पहुंच गई है. विकास कार्य करने के लिए बड़े प्रमाण में पेड़ों की कटाई की जा रही है. पिछले कुछ वर्षों में पुराने विशालकाय पेड़ों को सड़क चौड़ाईकरण के नाम पर काटा गया. जिस प्रकार पेड़ों की कटाई की गई है उसकी तुलना में नये पौधे रोपित नहीं किए गए. रोपित किए भी गए तो उनका जतन नहीं किया गया, जिसके कारण ये पौधे 'मृत' हो गए. पेड़ों की संख्या घटने के कारण पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ रहा है. पिछले कुछ वर्षों से धूल के कण प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, ऐसी जानकारी जांच के बाद सामने आई है. वाहनों से निकलने वाले धुएं के कण से, सड़क की धूल से इसके अलावा विविध सूक्ष्म कण एकत्रित होने से धूल के कण का प्रदूषण बढ़ रहा है. ऐसी जानकारी सामने आई है. निवासी क्षेत्र में आरएसपीएम अर्थात धूल के कणों के प्रमाण 100 माइक्रोग्राम पर मीटरक्यूब मिला है. निवासी क्षेत्रों में धूल के कण का प्रदूषण साधारण स्थिति में है. लेकिन इस ेर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. भविष्य में धूल के कणों के कारण अमरावती वासियों के फेफड़ों पर बूरा असर पड़ने की संभावना निर्माण हुई है.

शहर विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है, पर पर्यावरण समस्या जस की तस बरकरार है. नियोजन पर मार्गक्रमण व कार्रवाई के लिए प्रशासन व सामान्य नागरिकों को मार्गदर्शक के रूप में उपलब्ध पर्यावरण की रिपोर्ट ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इस रिपोर्ट को तैयार करते समय पर्यावरण के विविध घटकों की विभाग के माध्यम से जांच के बाद उपाय योजना, शाश्वत पद्धत से मूलभूत सुविधा विकसित करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े कानून पर अमल करने का सुझाव रिपोर्ट में है. पर्यावरण रिपोर्ट तैयार करते समय 2015-16 की रिपोर्ट को आधारभूत ग्रहित मानकर रिपोर्ट को नूतनीकृत किया गया है. शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय के साथ समझौता किया गया है. शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2016-17 की रिपोर्ट सीएसआर एक्टिविटी में तैयार किया गया है. शहर के पर्यावरण की वर्तमान में रिपोर्ट महापालिका के आमसभा के समक्ष रखी गयी. मात्र अधिकारी-कर्मियों की हड़ताल के कारण उस पर चर्चा नहीं हो पाई. आगामी सभा में उक्त मुद्दे पर घमासान होने की संभावना निर्माण हुई है.

धूलकण का स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम

धूलकण के कारण हृदय की दैनंदिन कार्यशक्ति धीमी हो सकती है. सिलिकुसिस नामक बीमारी हो सकती है. पर्यावरण में प्रदूषण के कारण आंखों में जलन भी होती है. समय रहते प्रदूषण पर काबू नहीं पाया गया तो इसका विपरीत परिणाम हो सकता है.

प्रतिवर्ष 10 हजार पौधों के रोपण की जरूरत

शहरीकरण के कारण बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 10 हजार पौधों का रोपण व संगोपन करना समय की मांग है. रिपोर्ट में इसका उल्लेख है. वृक्षों के कारण प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है, ऐसा पर्यावरण प्रेमियों का कहना है.

अक्स अमरावती का

इनरव्हील व समर्पिता का बालवाड़ी को सहयोग

यावली शहीद की डॉ. गोविंद कासट मित्र मंडली द्वारा संचालित बालवाड़ी को इनरव्हील क्लब व समर्पिता ग्रुफ की ओर से वॉटर बॉटल, शैक्षणिक चार्ट, अल्पोहार आदि के लिए सहयोग किया.

अद्वैत की फिल्म संकलन कार्यशाला उद्घाटित

ज्येष्ठ नाटककर्मी व संगीत दिग्दर्शक व मार्गदर्शक विनय सोनुले, विवेक चक्रे की उपस्थिति में अद्वैत संस्था की ओर से आयोजित फिल्म संकलन कार्यशाला का उद्घाटन किया गया.

साठे समिति व लहुजी सेना द्वारा अभिवादन

अण्णाभाऊ साठे की पुण्यतिथी निमित्त शहर के राजकमल चौक पर अण्णाभाऊ साठे पुतला समिति व लहुजी शक्ति सेना की ओर से उनकी प्रतिमा पर हारार्पण कर अभिवादन किया गया.

गुरु पूर्णिमा पर ताजणे का सम्मान

बाबा आमटे के आनंदवन में विकलांग कर्मशाला के अधिक्षक सदाशिव ताजने का गुरु पूर्णिमा निमित्त डॉ. गोविंद कासट मित्र मंडली की ओर से सम्मान किया गया. दिलीप सदार, उमेश धुमाले, उपसिथत थे.

विवि ऑडिट के लिए 31 तक डेडलाइन

वित्त विभाग के समक्ष चुनौती, विवि कानून प्रावधान से होगी अड़चन

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती - महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय कानून के अनुसार संगाबा विवि को किसी भी सूरत में 31 जुलाई तक बीते वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षण करना अनिवार्य है. जिससे विवि वित्त विभाग के समक्ष चुनौती निर्माण हुई है.महाराष्ट्र विवि कानून 1994 के प्रावधान अनुसार अब तक वित्तीय वर्ष खत्म होने के 6 माह के भीतर विवि का ऑडिट करना आवश्यक था. 1 मार्च 2017 से लागू नए विवि कानून के अनुसार वित्तीय वर्ष खत्म होने के चार माह के भीतर ऑडिट करना आवश्यक है. यह अवधि 31 जुलाई को खत्म होने जा रही है. अब तक की परंपरानुसार वित्त विभाग ने अभी तक कोई तैयारी नहीं करने की जानकारी है. 31 जुलाई के पूर्व विवि का लेखा परीक्षण पूर्ण होने की संभावना नहीं है.

विवि कानून में ऑडिट की डेडलाइन देने से विवि के समक्ष मुश्किलें आ सकती हैं. विवि के वित्त विभाग की ओर अभी भी करोड़ों रुपयों का एडवान्स हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया. 'प्रतिदिन अखबार' ने यह बात उजागर की है. अभी तक करोड़ों का हिसाब-किताब न होने से 31जुलाई तक होगा भी या नहीं, इसकी संभावना नहीं.

क्या कहता है कानून ?

वित्तीय वर्ष खत्म होने के चार माह पूर्व ऑडिट कर लेखा परीक्षण अहवाल प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अहवाल में दर्ज अभिप्राय का अनुपालन कर उसकी विसंगतियों का अहवाल विवि प्रकाशित करेगा. उसकी एक कॉपी सालभर पहले कुलपति और राज्य सरकार को भेजनी होगी.

...तो होगा कानून का उल्लंघन

विश्वविद्यालय के लेखा परीक्षण एक साल के भीतर पूर्ण न होने पर सीधे-सीधे विवि कानून का उल्लंघन रहेगा. इसलिए वित्त विभाग का गहराई से ज्ञान रखने वाले अधिकारियों को विवि कानून की ओर ध्यान तो नहीं? यह सवाल भी विवि परिसर में निर्माण हुआ है.

माहेश्वरी पंचायत की कार्यकारिणी का अभिनंदन

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती- अमरावती माहेश्वरी पंचायत के चुनाव हाल ही संपन्न हुए. चुनाव में सरपंच (अध्यक्ष) व सभी कार्यकारिणी सदस्यों का चयन निर्विरोध व शांतिपूर्वक संपन्न हुए. चुनाव में सभी माहेश्वरी बंधुओं ने आपसी समन्वय, तालमेल, टीम भावना व कार्य करने वालों सदस्यों का निर्विरोध कार्य करने का अवसर दिया है. ऐसे विचार आनंद मालपानी ने व्यक्त कर शहर के सभी माहेश्वरी बंधुओं का तहेदिल आभार माना. साथ ही विजयबाबू करवा व समस्त नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए आगामी कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी.

युवक बिरादरी के महासंचालक विदर्भ की यात्रा पर

27 व 29 को स्वयं से उद्यम कार्यशाला

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती- युवक बिरादरी भारत के महासंचालक आशुतोष शिरके 27 से 29 जुलाई तक विदर्भ की यात्रा पर पधार रहे हैं. 27 को दर्यापुर व 28 को अमरावती शहर के छात्रों का स्वयं से उद्यम कार्यशाला के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे. युवक बिरादरी के अध्यक्ष अभिषेक बच्चन के मार्गदर्शन में 'स्वयं से उद्यम' कार्यशाला उपक्रम का निर्माण किया. छात्रों को सफल करियर और नौकरी के दायरे से बाहर जाकर उद्योग क्षेत्र में करियर की नई राह तलाशने और उसके अवसर को लेकर मार्गदर्शन किया गया है.

बुधवार, 26 जुलाई की शाम शिरके का स्थानीय विश्रामगृह में आगमन होगा. 27 जुलाई की सुबह 10 बजे दर्यापुर के युवक बिरादरी सेंटर के प्रतिनिधियों की बैठक लेंगे. दोपहर 12 बजे नजमा पटेल जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस के छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे. 27 जुलाई की शाम अमरावती जिला युवक बिरादरी की बैठक को संबोधित करेंगे. 28 जुलाई की सुबह 9 बजे राजापेठ स्थित भारतीय महाविद्यालय में कार्यशाला लेंगे. अकोला स्थित सीताबाई आर्ट्स कॉलेज में दोपहर 1 बजे मार्गदर्शन करेंगे. 29 जुलाई की सुबह 9 बजे बुलढाणा स्थित जिजामाता महाविद्यालय में छात्रों की कार्यशाला को संबोधित करेंगे. कार्यशाला का लाभ विदर्भ के युवक-युवतियों को लेने की अपील विदर्भ युवक बिरादरी के अध्यक्ष प्रा. विजय लुंगे, समन्वयक गौरव इंगले, जिलाध्यक्ष डॉ. विनय तिड़के, अकोला जिलाध्यक्ष प्रा. विजय कौशल, दर्यापुर युवक बिरादरी के प्रदीप चौधरी ने की है.

'उर्जिता 2017' खेल महोत्सव दिसम्बर में

अभा माहेश्वरी महिला संगठन का उपक्रम

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती- अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से 16 से 20 दिसम्बर को 'उर्जिता 2017' खेल महोत्सव का भव्य आयोजन पेस सर्कल क्लब, कलकत्ता में किया जा रहा है. खेल महोत्सव में 5 अंचलों के 27 प्रदेश सहभाग ले रहे है. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य माहेश्वरी नवयुवतियों एवं महिलाओं की खेल कौशल भावना को राष्ट्रीय स्तरी पर विशेष अवसर एवं सम्मान प्राप्त हो. जिससे उनके सुप्त खेल की प्रतिभा विकसित हो और वे उसे श्रेष्ठतम तरीके से प्रदर्शित कर सके. महोत्सव में क्रिकेट, बास्केटबॉल, बेडमिंटन, कैरम एवं चेस प्रतियोगीता का समावेश है. राष्ट्र के 5 अंचलों के बीच अंतरराष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत ही सभी खेल खेले जाएंगे. मध्यांचल के तहत विदर्भ प्रदेश से भी सभी ग्यारह जिलों से श्रेष्ठतम खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है. सभी प्रतियोगीता में सहभाग लेने हेतु माहेश्वरी नवयुवतियों एवं महिलाओं की आयु मर्यादा 18 से 40 वर्ष तक तथा वे जिला, प्रदेश की टीमों में अपना प्रदर्शन कर चुकी हो.

इच्छुक चयन प्रक्रिया में अपने प्रमाणपत्र के साथ उपस्थित रहे तथा अपने नाम 15 से 20 अगस्त तक विदर्भ अध्यक्ष उषा करवा 9423123153, सचिव भारती राठी 9423146244, ज्योति बाहेती 9423088950 व नीता मुंदडा 9403311633 पर संपर्क कर सकते है. प्राप्त आवेदन से श्रेष्ठतम खिलाड़ियों का चयन होकर उनकी प्रतिभाओं को श्रेष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकेगा. उक्त जानकारी प्रचारमंत्री शशी मुंदडा ने दी है.

12 आंदोलनकारियों पर दर्ज मामले वापस लें

सीएम से विधायक यशोमति की मांग

अमरावती- तिवसा तहसील के शिरजगांव मोझरी में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने से 12 युवकों ने आंदोलन किया था. आंदोलन के समय उनके खिलाफ तिवसा पुलिस ने मामले दर्ज किये थे. इन मामलों को वापस लेने की मांग विधायक यशोमती ठाकुर ने सीए देवेंद्र फड़णवीस से की है. शिरजगांव मोझरी ग्राम पंचायत के नियोजन के अभाव से भीषण जलकिल्लत समस्या निर्माण हुई थी. इस बारे में ग्राम पंचायत पदाधिकारी व सचिव को बार-बार निवेदन देने के बावजूद समस्या हल न होने से 18 अप्रैल 2017 को ग्राम पंचायत कार्यालय को पूर्व सूचना देकर ताला ठोका गया था. ग्राम पंचायत सचिव ने 19 अप्रैल को 12 युवकों के खिलाफ तिवसा पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था. सचिव ने मामला दर्ज कराने के बाद रातभर किसी भी प्रकार के काम का संबंधित इस्टीमेट व आदेश न देकर सचिव ने पानी वितरण समस्या सुचारू की थी. इस बारे में यह बात ध्यान में लेकर पानी संबंधित किये गये जनहितार्थ आंदोलन में युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज किये थे. इसीलिए इन मामलों को वापस लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग विधायक यशोमती ठाकुर ने सीएम देवेंद्र फड़णवीस से की है.

किसानों को 50 हजार रु. की आर्थिक मदद दें

युवा स्वाभिमान पार्टी की राज्य सरकार से मांग

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती- जिले में बीते कुछ दिनों से बारिश न होने से जिले के किसानों पर दोबारा बुआई की नौबत आन पड़ी है. भातकुली समेत अंजनगांव सुर्जी, दर्यापुर, नांदगांव खंडेश्वर, चांदूर बाजार, मोर्शी व अमरावती जिले की कुछ तहसीलों में तीसरी बार बुआई करने की नौबत आन पड़ी है. आर्थिक अड़चनों का सामना कर रहे किसानों को राज्य सरकार प्रति हेक्टेयर 50 हजार रु. की मदद करे, ऐसी मांग युवा स्वाभिमानी पार्टी की ओर से की है.

युवा स्वाभिमानी पार्टी की ओर से जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया है. ज्ञापन के मुताबिक इस वर्ष मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की संभावना जताई थी. जिसके आधार पर किसानों ने समय पर बुआई की. लेकिन इस बीच बारिश न होने से किसानों पर दोहरी बुआई का संकट आन पड़ा. मौसम विभाग का अंदाजा सही नहीं हुआ. जिससे किसानों पर आर्थिक भुर्दंड बढ़ा. जैसे-तैसे कर किसानों ने पहली बुआई की. पुनः दूसरी बुआई को लेकर किसान चिंतित हैं.

किसानों को चिंता से मुक्त करने के लिए शासन 50 हजार रु. प्रति हेक्टेयर अनुदान किसानों दे. ज्ञापन सौंपते वक्त राजू रोडगे, संजय हिंगासपुरे, महानंदा पवार, गिरीश कासट, मयूरी कावरे, निदेश टेकाम, जया तेलखड़े, मिनल डकरे, रश्मि घुले, प्रदीप थोरात, उमेश ढोणे, मंगेश इंगोले, बाबू पाटिल, सतीश मंत्री, रामदास रंगारी, ज्ञानेश्वर कलस्कर आदि उपस्थित थे.

विवि में 20 वीं राष्ट्रीय परिषद 29 से

अमरावती- संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय के वनस्पतिशास्त्र विभाग व इंडीयन एरोबॉयलॉजीकल सोयाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 29 से 31 जनवरी 2018 में 20 वें राष्ट्रीय परिषद का आयोजन विश्वविद्यालय में किया गया है. 'एआरबोर्न पोलन एंड स्पोर्स : एसेसमेंट, इम्पेक्ट एंड स्कोप' थीम पर आयोजि राष्ट्रीय परिषद की विस्तृत जानकारी विवि के डब्लूडब्लूडब्लू.एसजीबीएयू.एसी.इन पर उपलब्ध है. सहभाग हेतु इच्छुक अपना पंजीयन 30 नवंबर तक कर सकता है. राष्ट्रीय परिषद आयोजन हेतु कुलगुरु डॉ. मुरलीधर चांदेकर के मार्गदर्शन में विविध समितियों को गठन किया गया है. अधिक जानकारी के लिए वनस्पतिशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. जयकिरण तिडके से संपर्क करने का आह्वान विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है.

महाभाष्य प्रवचन समारोह शुरू

अमरावती- श्री स्वामी चक्रधर स्वामी के शास्त्र पर मार्गदर्शन तथा ब्रह्मविद्या शास्त्रांतर्गत महाभाष्य प्रवचन समारोह का शुभारंभ किया गया है. स्थानीय माताखिड़की स्थित श्रीकृष्ण मंदिर देवस्थान में अमरावती वासनीक सेवा मंडल की ओर से आयोजित समारोह शाम 7 से 8.30 बजे दौरान शुरू है. समारोह का समापन आगामी शनिवार, 5 अगस्त को किया जाएगा.

खोलापुरी गेट का कचरा डिपो बना जानलेवा

अमरावती- अमरावती मनपा क्षेत्र में स्थित खोलापुरी गेट के समक्ष कचरा डिपो को शहर से 15 किमी की दूरी पर हटाने का निवेदन 'आप' पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से निवासी जिलाधिकारी व मनपा आयुक्त को 18 जुलाई को सौंपा गया. निवेदन में उल्लेख किया गया है कि यह कचरा डिपो शासकीय नियमानुसार नहीं है तथा शहर से अत्यंत नजदीक होने के कारण यह

कंपोस्ट डिपो शहरवासियों के लिए जानलेवा बन चुका है. इस डिपो की खुली जगह पर कचरा जलाया जाता है. जिसके धूएं से प्रदूषण फैलता है और परिसर में बीमारियां हो रही हैं. इसके अलावा मृत जानवरों को भी यहां फेंका जाता है. कभी-कभी तो आवारा कुत्ते व अन्य जानवर कचरे को बस्ती में घसीटकर ले आते हैं. इस डिपो में कचरे के ढेर 70-80 फीट तक ऊंचे चले गए हैं और इन ढेरों में बरसात का पानी जमा होकर उसमें से दुर्गंध फैलने लगी है.इस संबंध में अनेकों बार मनपा प्रशासन को सूचना दी गई, किंतु प्रशासन द्वारा आज तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई. अतः आम आदमी पार्टी ने मनपा प्रशासन से निवेदन किया है कि, एक माह के भीतर यदि प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा. निवेदन सौंपने वालों में अफसरभाई, नितीन गवली, संजय शहाकार, विरेंद्र उपाध्याय, मदन शेलके, अ. बशीर शेख, महेश देशमुख, वी.एस. पाटिल, अर्जुन सरदार आदि सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का समावेश था.

'आप' का जिलाधीश व मनपा आयुक्त को ज्ञापन

प्रतिदिन अखबार
सूचना

प्रतिदिन अखबार के पाठकों को सूचित किया जाता है कि वे इस अखबार में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में उल्लेखित उत्पादनों की गुणवत्ता जाँच-पड़ताल करने के बाद ही उसे खरीदने आदि के संबंध में निर्णय लें व आर्थिक व्यवहार करें. अपने उत्पाद अथवा सेवा के संदर्भ में विज्ञापनदाता जो दावे पेश करते हैं, प्रतिदिन अखबार उसकी कोई गारंटी नहीं देता. कृपया नोट करें कि विज्ञापित उत्पादों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता (उत्पादक) अथवा संबंधित नहीं करते तो उसके परिणामों के लिए प्रतिदिन अखबार के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक व मालिक जिम्मेदार नहीं होंगे.

- व्यवस्थापक

कर्जमाफी लाभ के लिए जिले में 600 से अधिक सेंटर शुरू

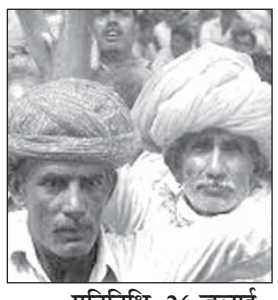

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती- राज्य सरकार द्वारा घोषित कर्जमाफी का लाभ पाने के लिए शहर समेत जिले में 600 से अधिक ऑनलाइन सेंटर शुरू कर दिये गये हैं. जहां किसानों को कर्जमाफी के लिए आवेदन करना है. कर्ज के बोझ तले दबे किसानों समेत नियमित कर्ज भरने वाले भूमिपुत्रों को भी 25 हजार रुपये का अनुदान पाने ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है.

समस्याओं से जूझ रहे

लाभार्थी किसानों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है. जैसे ही इस योजना की जानकारी मिली तो लाभार्थियों ने बैंक के चक्कर लगाना आरंभ कर दिया. लेकिन पात्र लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना है. यह जब पता चला तो कुछ किसानों ने आपले पोर्टल पर इस योजना के लिए पंजीयन करने का प्रयास किया किंतु इंटरनेट नहीं रहना, बिजली नहीं रहना, नेट धीमी गति से चलने जैसी समस्याओं का सामना भी ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को करना पड़ रहा है.

किसान ऑनलाइन आवेदन करें

एकमात्र आधार जरूरी

राज्य सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना 2017 घोषित की है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन सेंटर के माध्यम से आवेदन भरकर देना होगा, जिसके लिए प्रशासन द्वारा 600 से अधिक सेंटर शुरू किये हैं.

हाल ही में घोषित सेंटर में लाभार्थियों के आवेदन कैसे भरना है इसका प्रशिक्षण दिया गया. इन सेंटर में जिले के महा-ई-सेवा केंद्र, सेतु, संग्राम केंद्रों समेत साइबर कैफे के साथ ही कुछ गिने-चुने सरकारी कार्यालयों का समावेश किया है.आपले सरकार पोर्टल पर आवेदनकर्ता द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार क्रमांक अथवा नहीं रहने पर आधार क्रमांक के लिए पंजीयन कर प्राप्त होने वाला आयडी क्रमांक जरूरी है.

सेंटर चालकों को दिया प्रशिक्षण

आरडीसी डॉ. नितिन व्यवहारे ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए हाल ही में सेंटर चालकों को प्रशिक्षण दिया है. अब आवेदनकर्ता यदि सेंटर पर पहुंचकर फार्म भरते हैं उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सभी जानकारी और अत्यावश्यक दस्तावेज समेत सभी प्रशिक्षण दिया है.

ऑनलाइन दिखेगी संख्या

गौतम वालदे, जिला उपनिबंधक ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन कितने और कौन से तहसील के किसानों ने किये हैं इसकी जानकारी आपले सरकार पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही है जिसके चलते राज्य सरकार को यह संख्या पोर्टल पर दिखाई देने का प्रस्ताव भेजा है.

निधि के अभाव में खस्ताहाल पुल्लों का मरम्मत कार्य लटका

नागरिकों को हो रही परेशानी

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती- जिले में पुरातन खस्ताहाल पुलों की मरम्मत करने के लिए निर्देश दिए गए थे. जिसके तहत सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग द्वारा जिले के 28 खस्ताहाल पुलों की मरम्मत करने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक निधि प्राप्त नहीं होने से खस्ताहाल पुल का काम अधर में है, जिससे नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.बता दें कि बरसात के पूर्व जिले में निर्माण किए गए पुल व पुरातन खस्ताहाल पुलों की जांच पड़ताल कर जिलाधीश की मौजूदगी में बैठक ली गई थी. जहां निर्माण कार्य विभाग द्वारा जांच पड़ताल के पश्चात जिले के 28 खस्ताहाल पुलों

की मरम्मत करने की बात कही गई थी. जिसका निर्माणकार्य करने मंजूरी भी मिल चुकी थी, परंतु प्रस्ताव भेजने के बावजूद अब तक निधि नहीं मिलने से इसके पूर्व का कामकाज अधर में है, जहां किसी भी घड़ी कोई बड़ी अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता. इस बात से जिलाधीश को भी अवगत कराया जा चुका है.